भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1128
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी सोसाइटी का कम्प्यूटरीकरण

1128. **डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:**
श्री नारायण कोरागप्पा:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में चल रही सहकारी सोसाइटी की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) कर्नाटक में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) सहित सहकारी सोसाइटी का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में सभी सहकारी सोसाइटी को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है और इस उद्देश्य के लिए 2,516 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं;
(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में कम्प्यूटरीकृत की जाने वाली सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और
(ङ) क्या कर्नाटक में किसी बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी में परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिनांक 07.12.2023 तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 7,96,344 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। कर्नाटक राज्य में 44,245 सहकारी समितियां हैं जिनमें 6,084 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) भी शामिल हैं। सहकारी समितियों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(ग) एवं (घ): पैक्स को मजबूत करने हेतु, भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ERP (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है, जिससे उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ा जाना शामिल है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से पैक्स की परिचालन दक्षता में सुधार करने, ऋणों का शीघ्र संवितरण सुनिश्चित करने, लेनदेन लागत को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना के

गाइडलाइन्स के अनुसार, पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को मार्च, 2025 तक पूरा किया जाना है और मार्च, 2027 तक हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जाएगी।

28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 62,318 पैक्स को कर्नाटक राज्य के 5,491 पैक्स सहित कम्प्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। नाबार्ड द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है और देश में 5,673 पैक्स में ईआरपी ट्रायल रन शुरू हो गया है। कर्नाटक राज्य सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर खरीद और लीगेसी डाटा का डिजिटलीकरण प्रक्रियाधीन है ।

(ङ): कर्नाटक राज्य में कोई बहु-राज्य सहकारी समिति परिसमापन के अधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक

देश में सहकारी समितियों की दिनांक 07.12.2023 तक संख्या

क्र.सं	नाम	सहकारी समितियों की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	8,615
2	हिमाचल प्रदेश	5,116
3	पंजाब	19,032
4	चंडीगढ़	476
5	उत्तराखंड	5,289
6	हरियाणा	32,353
7	दिल्ली	5,943
8	राजस्थान	36,816
9	उत्तर प्रदेश	43,460
10	बिहार	26,640
11	सिक्किम	3,789
12	अरुणाचल प्रदेश	1,166
13	नागालैंड	8,118
14	मणिपुर	9,795
15	मिजोरम	1,222
16	त्रिपुरा	3,142
17	मेघालय	2,646
18	असम	11,073
19	पश्चिम बंगाल	31,190
20	झारखंड	11,407
21	ओडिशा	6,780
22	छत्तीसगढ	8,971
23	मध्य प्रदेश	51,702
24	गुजरात	81,024
25	महाराष्ट्र	222,053
26	आंध्र प्रदेश	17,659
27	कर्नाटक	44,245
28	गोवा	5,439
29	लक्षद्वीप	35
30	केरल	6,103
31	तमिलनाडु	21,481
32	पुदुचेरी	457
33	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,204
34	तेलंगाना	60,107
35	लद्दाख	267
36	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	529
	कुल	**7,96,344**

नोट: केरल और मणिपुर को छोड़कर राज्यों द्वारा 97% डेटा प्रविष्टि पूरी कर ली गई है ।